है तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी नीयत बेइमानी करने की नहीं है। आज हिन्दुस्तान में जो व्यर्थ का पैसा इस संस्था पर खर्च हो रहा है उसके कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को मिलाकर, 1971–72 में 82 थी जोकि 72–73 में 87 रही। 1972–73 में मात्र तनख्वाह का खर्चा 3,37,800 रु० था। इसके साथ साथ जो अन्य सुविधायें मिलती हैं जैसे मैडिकल फैसिलिटीज, किराया भाड़ा इत्यादि वह अलग है। इसी प्रकार से बिहार विधान परिषद् में 1975–76 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते का खर्चा 36,848 और 1976–77 में 48,000 तथा 1977–78 में 58,000 है। यह मात्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता है। इसी प्रकार सदस्यों के ऊपर 23,62,700 रुपए का खर्चा हुआ। इसी तरह से 1976–77 और 1977–78 में 23,67,200 रुपया का खर्चा है। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में 1973–74 में 3,46,800 रुपए का खर्चा हुआ (व्यवधान) इससे मेरा मतलब यह है कि लाखों रुपया और कुल मिलाकर करोड़ों रुपया विधान परिषदों में खर्च किया जा रहा है जिसका कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी इस पर पुनः विचार करें और राष्ट्रीय पैमाने पर मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाकर उनको आदेश दें कि अविलम्ब विधान परिषदों को समाप्त किया जाये।

MR. CHAIRMAN: Are you withdrawing the Resolution, as requested by the hon. Minister?

श्री रामजी लाल सुमन : मैं विदड्रा नहीं करना चाहता। अगर यह प्रस्ताव यहां पर पास नहीं होता है तो सारे देश में इसके लिए एक राष्ट्रीय आन्दोलन चलाने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि अगर मैं इसको वापिस लेता हूं तो इसका मतलब होगा कि जो कुछ मैंने कहा है उसको वापिस ले रहा हूं।

श्री शान्ति भूषण : रेजोल्यूशन वापिस लेने का मतलब यह नहीं होता कि जो आपने भाषण दिया है वह भी वापिस हो गया।

MR. CHAIRMAN: Now I will put the Resolution moved by Shri Ramji Lal Suman to the vote of the House.

The question is:

"This House is of the opinion that the Upper House (Legislative Councils) in the States have not served any useful purpose and in the process of legislation they are proving to be cumbersome and avoidably expensive and, therefore, the Constitution should be suitably amended to abolish them as soon as possible."

The motion was negatived.

16.15 hrs.

RESOLUTION RE PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM TO CHECK RISING PRICES

SHRIMATI AHILYA P. RANGNEKAR (Bombay North-Central): Sir, I am moving my Resolution. I beg to move:

"This House expresses its grave concern at the steep rise in the prices of all essential commodities

[Shrimati Ahilya P. Rangnekar]

like pulses, edible oils, milk, cloth, footwear, soap, etc. and fall in the prices of all commercial crops like sugarcane, cotton, tobacco etc. and recommends that, with a view to protect the primary producers as well as the consumers, all essential commodities be procured through the State Governments at fair price from the producers and distributed to the consumers through an effective public distribution system supervised by People's Committees to be set up for this purpose."

सभापति महोदय, मुझे दुःख है कि हमारे सिविल सप्लाईज और कामर्स के मिनिस्टर, श्री मोहन धारिया जी, इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं। हम रोज अखबारों में मंत्रियों और दूसरे लोगों के बयान पढ़ते हैं कि हमारी जरूरत की चीजों के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन यह सच्चाई नहीं है, कीमतें हर रोज बढ़ती जा रही हैं। फरवरी, 1978 से लेकर मार्च, 1978 तक एक ही महीने में होल-सेल प्राइस इण्डेक्स .68 बढ़ गया है। इन कीमतों के बढ़ने से हमारी सामान्य घरेलू औरतों के सामने एक कठिनाई उत्पन्न हो गई है।

आप देखिए—फूड आर्टीकल्ज का फरवरी, 1978 में प्राइस इन्डक्स 169.1 था, लेकिन एक महीने के बाद 169.9 हो गया, .8 बढ़ गया। ये फिगर्स होल-सेल प्राइस इंडेक्स की हैं, रिटेल की नहीं है, रिटेल में तो दुगने और तिगुने दाम बढ़ गये हैं। फूड ग्रेन्ज में फरवरी में प्राइस इन्डेक्स 172 था, लेकिन मार्च में 173.1 हो गया। पलसेज में फरवरी में 243.5 था, जो मार्च में बढ़ कर 247.4 हो गया, इस तरह से एक महीने में पलसेज के दाम 3.9 बढ़ गये। फ्यूअल, पावर, लाइट और लुब्रिकेण्ट्स में 3.54 की बढ़ोतरी एक महीने में हुई है। शुगर-खाण्डसारी के लिए कहा जाता था कि दाम कम हुए हैं, लेकिन इस में भी इस पीरियड में 1.5 की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेन्ट में भी दाम बढ़े हैं, कैमिकल्ज में भी दाम बढ़े हैं। आज जरूरत की कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जिस में होल-सेल प्राइस इंडेक्स कम हुआ हो।

छोटी-छोटी चीजें, जिनकी औरतों को रोज जरूरत पड़ती है, जैसे धनिया, उस के दाम 40 से 50 पैसे किलो हो गये हैं, लाल मिर्च का दाम साढ़े पांच रुपये किलो था, लेकिन उस का दाम अब सवा-छः रुपये किलो हो गया है। आप ने बजट के मौके पर शुगर की एक्साइज ड्यूटी कम की थी, उसके बावजूद भी उस समय शुगर के दाम बढ़े थे। इस साल हर चीज का उत्पादन बढ़ा है। लोग कहते हैं कि उत्पादन कम हो और डिमांड ज्यादा हो तो दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन इस साल तो हर चीज का मैक्सीमम प्रोडक्शन हुआ है, फिर भी कीमतें बढ़ रही हैं; इस का क्या कारण है? इस का एक ही कारण है कि ट्रेडर्ज जान-बूझ कर कीमतें बढ़ा रहे हैं, वे माल को अपने गोदामों में होर्ड कर रहे हैं और हमारी सरकार को इस की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यह आपस के झगड़ों में लगी हुई है। लोगों की तकलीफ़ों के बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं है, वह इस में कोई दखल नहीं दे रही है।

एक और बात आप को बतलाती हूं—चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, जब कि प्रोडक्शन हर चीज का बढ़ रहा है। काटन का प्रोडक्शन बढ़ गया, शुगर-केन का प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन कपड़े के दाम बढ़ने और शुगर के दाम बढ़ने का लाभ उस के उत्पादक को नहीं मिला। जो काटन का उत्पादन करता है, जो शुगर-केन का उत्पादन करता है, उसकी कीमतें उल्टा कम हो गई, उसको कम दाम मिले, लेकिन मिल मालिकों

को, जो जूता बनाते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं, उन को उस का लाभ मिला। हमारी सरकार का एक नया तरीका चल पड़ा है—जिस चीज की कीमत बढ़ जाती है, वह उस चीज का इम्पोर्ट करना शुरू कर देती है, यह देखने का प्रयास नहीं करती है कि उस वस्तु की कीमत क्यों बढ़ी है। जैसे ब्लेड की कीमत बढ़ गई है, तो उसका इम्पोर्ट शुरू कर दिया है। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं—सोडा-ऐश का। सभापति महोदय, सोडा ऐश कांच के उत्पादन में लगता है और सोडा ऐश का प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ गया है और यह 1800 रु० प्रति टन हो गया है जो कि पूरे देश की जो सोडा ऐश की जरूरत है उस से ज्यादा है लेकिन फिर भी इस को बाहर से मंगाने की बात की जाती है। सोडा ऐश का उत्पादन किस के हाथ में है? 56 परसेंट टाटा, 33 परसेन्ट बिरला, 7 परसेंट जैन के हाथ में और साहू के हाथ में 4 परसेंट है। इस तरह से बड़े लोगों के हाथों में इस का उत्पादन है और हमारे देश की जनता को जितनी इस की आवश्यकता है, उस से ज्यादा उत्पादन है लेकिन कीमतें इन्होंने बढ़ा दी हैं। पहले 1200 रुपये टन इस की कीमत थी, जिस को बढ़ा कर इन्होंने 1900 रुपये टन कर दिया है और हमारी जो यह गवर्नमेंट है, इस ने इस बारे में क्या किया? जब इन लोगों से पूछा गया कि इस की कीमत इतनी क्यों बढ़ गई है, 1200 रुपये प्रति टन से बढ़ कर 1900 रुपये प्रति टन क्यों इस की कीमत हो गई है, जो बहुगुणा जी कहते हैं कि हम सोडा एश इम्पोर्ट करेंगे। हर चीज इम्पोर्ट करने की बात करते हैं और यह नहीं देखते हैं कि कीमतें क्यों बढ़ गई हैं। ये जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इन के मुनाफ़े बहुत बढ़ गये हैं। इमर्जेन्सी के दिनों में इन के प्रॉफिट इतने बढ़ गये हैं कि एक कम्पनी जिस का प्रोफिट 20 करोड़ रुपये था, वह बढ़ कर 222 करोड़ रुपये हो गया। यह इसलिए होता है कि हम को मजबूर करते देते हैं और जब पूछते हैं कि इस को रोकने के लिए क्या रास्ता निकाला है, तो कहते हैं कि हम इम्पोर्ट करेंगे, सोडा एश इम्पोर्ट करेंगे। आज जो सिलिकोन के कारखाने हैं, कांच के कारखाने हैं, वे बन्द हो गये हैं और हजारों मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ़ नहीं जा रहा है।

इसी तरह से तेल की बात है। तेल के बारे में कहते हैं कि हम इम्पोर्ट करेंगे और इम्पोर्ट करने के बाद क्या होता है। अभी इकोनामिक्स टाइम्स में एक लेख निकला था, जिस में बताया गया था कि जो तेल इम्पोर्ट किया गया था, वह बम्बई में पड़ा रहा। वह खाने लायक नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस को दूसरे देशों में भेजेंगे और इस से हमें फारेन एक्सचेन्ज मिलेगी। फारेन एक्सचेंज कमाने के लिए जो चीज बाहर से आती है, उस को भी बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इस तरह का आप का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का तरीका चल रहा है। इसलिए कोई सही रास्ता इस के हल के लिए नहीं निकाला जा रहा है।

वेजीटेबल्स की प्राइसेज आप देखिए कि कितनी बढ़ गई हैं। मेरे पास बहुत सी फीगर्स हैं लेकिन मैं टाइम ज्यादा न होने के कारण सिर्फ प्याज का ही उदाहरण लेती हूं। जो प्याज पहले 75 पैसे किलो बिक रही थी, वह अब 1 रु० 40 पैसे और 1 रु० 50 पैसे किलो बिक रही है। जो प्याज पैदा करता है, उस किसान को प्याज का कितना मूल्य दिया जाता है? उस किसान से प्याज 25 पैसे किलो के हिसाब से आती है और बाजार में आ कर 1 रु० 40 पैसे और 1 रु० 50 पैसे बिकती है। बीच में इतना पैसा कौन ले जाता है? टमाटर की भी

[श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर]

यही हालत है। यह सब पैसा बीच के जो ट्रेडर्स हैं, वे ले जाते हैं। जब हम ने गवर्नमेंट से और श्री मोहन धारिया से इसके बारे में कहा, तो उन्होंने कहा कि हम स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन और नेफेड द्वारा उनसे डाइरेक्टली लेंगे और इस तरह से बीच का मुनाफ़ा कम हो जाएगा। हम ने पूछा था कि इस में खर्चा कितना आता है? अगर एक किलो पर 15 पैसे खर्च आते हैं, तो किसान को अगर 50 पैसे दे देंगे, तो बाजार में आ कर वह 60, 65 पैसे किलो कन्ज्यूमर्स को मिल सकता है, लेकिन जब नेफेड के अधिकारी वहां गये तो क्या हुआ कि ट्रेडर्स ने पहले से ही अच्छा माल अपने पास रख लिया और गन्दा माल नेफेड को दे दिया और ट्रेडर्स के बारे में आप उंगली नहीं उठाते हैं। ट्रेडर्स खुश हैं क्योंकि उन को मालूम है कि अगर वे प्राइसेज को रेज करते हैं तो गवर्नमेंट उन का कुछ करने वाली नहीं है। उल्टे उन को इम्पोर्ट करने के लिए और कन्सेशन्स सरकार दे रही है और इन कान्सेशन्स का वे फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तरफ़ वे प्राइस बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ़ उन को इम्पोर्ट लाइसेंस और दूसरे कन्सेशन्स सरकार दे रही है लेकिन इतने पर भी प्राइस कम नहीं हो रही हैं। गवर्नमेंट इस के बारे में कुछ नहीं कर रही है।

होर्डिंग के बारे में आप देखते हैं कि क्या हालत है। मैं आप को दालों की मिसाल देती हूं। बम्बई में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि एक हजार बोरी वहां दालों की हैं और इस से ज्यादा नहीं हैं। आप को मालूम होगा कि हम 100 औरतों को ले कर हर एक गोदाम में गये और छापा मारा। हमसे कहा गया था कि एक हजार बोरियां हैं, लेकिन हमें वहां दाल की 34 हजार बोरियां मिलीं। यह दाल के व्यापारियों की हालत है। आपको इन दाल के व्यापारियों की जांच करनी चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं कि इन दाल के व्यापारियों से सम्बन्धित इस हाउस में कौन है। उनसे सम्बन्धित लोग इस हाउस में जरूर हैं इसलिए दाल के व्यापारियों को संरक्षण मिल रहा है और वे भाव बढ़ाने की हिम्मत करते हैं। कहा जाता है कि दाल का उत्पादन कम है। मैं कहती हूं कि दाल का उत्पादन इतना कम नहीं है जितना कि इसके भाव बढ़े हैं। जब दाल का उत्पादन कम है तब भी किसान को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है जब किसान उत्पादन बढ़ाता है तब भी आप उसको प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। ये ट्रेडर लोग कमाते चले जा रहे हैं। इस सब की आपको जांच करनी चाहिए। दाल की कीमतें कम लाने के लिए आपको होर्डिंग बन्द करनी चाहिए।

हमारी गवर्नमेंट कहती है कि इन्फ़्लेशन कम हो रहा है। यह केवल दो परसेंट है। लेकिन हम देखते हैं कि यह कम नहीं हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर भी आपका कंट्रोल नहीं है। देश में काला पैसा बहुत है। आपने एक हजार रुपये के नोट बंद किये. इसका थोड़ा सा असर हुआ होगा लेकिन काला पैसा कम नहीं हुआ। आप सोने की नीलामी कर रहे हैं। नीलामी में सोना कौन खरीद रहा है? बड़े बड़े व्यापारी खरीद रहे हैं। आरडिनरी सुनार को सोना नहीं मिलता है। जब यह सोना भी बड़े-बड़े व्यापारी, बम्बई में रहने वाले बड़े बड़े ट्रेडर यह सोना ले जायेंगे और छोटे सुनार को यह नहीं मिलेगा तो इन्फ़्लेशन कैसे कम होगा? हम देखते हैं कि बम्बई में स्मगलिंग अभी भी हो रही है। बम्बई में रात को सिंथेटिक्स की स्मगलिंग होती है। स्मगलिंग पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इसी की वजह से सिंथेटिक्स के दाम बढ़ते हैं। हमने अभी देखा, दिल्ली में आपने डबल टोन शुरू

के दाम 15 पैसे बढ़ा दिये । आपको पता नहीं है कि आपके दूध के पाउडर की भी स्मगलिंग होती है और वह दूसरी कन्ट्रीज को जा रहा है । इस सब के बारे में गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ।

हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने सीमेंट की प्राइस भी बढ़ा दी । आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स सीमेंट का पूरा उत्पादन नहीं करते हैं । हमारी जितनी सीमेंट की प्रोडक्शन केपेसिटी है, वह पूरी अमल में नहीं आती है । आप देखेंगे कि हमारी प्रोडक्शन केपेसिटी का 20, 25 या 50 परसेंट तक ही उत्पादन होता है । अगर हम अपनी पूरी प्रोडक्शन केपेसिटीकाम में लायेंगे तो हमारा सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ेगा और इससे लोगों को सीमेंट की शार्टेज महसूस नहीं होगी ।

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट मैंने देखी है । रिपोर्ट में कहा जाता है कि मजदूर हड़ताल करते हैं इसलिए उत्पादन कम होता है । लेकिन आज भी जो लोक आऊट चल रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा जाता । इस सम्बन्ध में मैं इतना अवश्य कहूंगी कि इस लोक आऊट में जो लोग शामिल हैं वे कांग्रेस के एम० पीज० हैं । उन्होंने इसका प्रोग्राम चालू किया है । लोक आऊट को इल्लीगल करार दिया हुआ है फिर भी वह चल रहा है । यह सब क्यों हो रहा है ?

आपने कोयले पर एक्साइज ड्यटी बढ़ाई , उससे कोयले की कीमत बढ़ गई । शूगरकेन पर आपने एक्साइज ड्यटी कम कर दी, उससे शूगरकेन की कीमत तो कम हो गई लेकिन चीनी के दाम बढ़ गये । ये ट्रेडर्स लोग होर्डिंग करते हैं जिससे ये प्राइसिज और बढ़ जाती हैं । पहले चावल सस्ता मिलता था लेकिन अब कोई भी चावल दिल्ली में 6 रुपये किलो से कम नहीं मिलता है । आपने इसकी कीमतों पर रोक नहीं लगाई तो आप एक साल के बाद देखेंगे कि चावल पूरा का पूरा होर्डिंग में चला जाएगा और गरीब लोगों को कुछ नहीं मिलेगा । इसी तरह से सोप के बारे में । ये मल्टी निशियनर्स चेम्बर आफ कामर्स में मोहन धारिया जी को और मोरारजी भाई को हार पहनाते हैं और कहते हैं उन्होंने घोषणा की थी कि हम प्राइस फ़ीज करेंगे । उन्होंने कहा था कि 31 दिसम्बर तक प्राइस फ़ीज करके रखेंगे । क्या उन्होंने ऐसा किया है ? टाटा, बिड़ला वगैरह तक ने कीमत बढ़ा दी हैं । तीन महीने में ही बढ़ा दी हैं । एक तरफ मालाएं पहनाई जाती हैं और घोषणा की जाती है कि हम प्राइस फ़ोज करके रखेंगे और दूसरी तरफ 31 दिसम्बर, से पहले पहले 25—30

परसेंट प्राइसिस को बढ़ा दिया जाता है । बाकी की जो चीजें हैं वहां पर उन में तो 50—55 परसेंट बढ़ा दी गई हैं । क्या यह प्राइस फ़ीज हुआ है । एक और चालाकी उन्होंने चली है । साबुन में उन लोगों ने फैट कंटेंट को कम कर दिया है । साइज वही है, प्राइस अगर कम भी करदी है तो चालाकी यह की है कि फैट कंटेंट कम कर दिया है । माननीय ज्योतिर्मय बसु ने सवाल उठाया था तेल का । पोस्टमैन तेल बहुत चलता है बहुत मशहूर है । अगर इस में मिलावट होती है तो किस को पकड़ा जाता है ? मैनेजर को पकड़ा जाता है । क्यों नहीं मैं पूछना चाहती हूं कि चेयरमैन और ट्रस्टी को आप पकड़ते हैं । दूसरी जगह पर मिलावट होती है और कोई केस पकड़ा जाता है तो उस में आप आफिस में काम करने वाला जो चपड़ासी है उसको पकड़ते हैं । मैं पूछना चाहती हूं कि क्यों नहीं आप चेयरमैन और मैनेजर को पकड़ते हैं ? उनको आप छोड़ देते हैं और चपड़ासी को पकड़ लेते हैं मिलावट करने के

[श्रीमती अहिल्या पी० रांगणेकर]

जुर्म में। चेयरमैन को क्यों नहीं पकड़ते हैं। इन बड़े लोगों के खिलाफ़ आप कदम नहीं उठाते हैं। पुरानी सरकार का जो तरीका था वही तरीका आप ने भी अख्तयार कर रखा है। उसी तरीके से आपका काम भी चालू है। आप सीरियस नहीं हैं इन सब बातों के बारे में।

श्री मोहन धारिया ने कहा था जहां 20 हजार से ज्यादा लोगों की बस्ती है वहां हम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलेंगे। उन्होंने कहा था कि देश में 2 लाख 20 हजार इस तरह के सैंटर खुलने वाले हैं, छोटी छोटी सरकारी दुकानें खुलने वाली हैं। वहां पर लोगों को जरूरत की दस चीजें मिलेंगी। आपने चावल को छोड़ दिया था। आपने कहा था कि वहां पर तेल, मसाले, कपड़ा, कैरोसीन आयल, माचिस, सोप आदि इस तरह से दस चीजें मिलेंगी। उनकी घोषणा थी कि हम 2 लाख 20 हजार इस तरह के सैंटर खोलने वाले हैं उन जगहों पर जहां पर बीस हजार से अधिक की बस्ती है। इस घोषणा को किए हुए छः महीने से ज्यादा का समय हो गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि कितनी इस तरह की दुकानें आपने खोली हैं। अभी तक एक भी नहीं खोली है। आपके द्वारा एलान करने के बाद, आश्वासन देने के बाद छः महीने में एक सैंटर भी आपने नहीं खोला है तो आगे आप पर किस तरह से विश्वास किया जा सकता है।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो प्रोड्यूसर है उस को उसकी प्रोड्यूस की आपको उचित कीमत भी देनी चाहिए। एस टी सी की स्थापना आपने कर रखी है। लेकिन वहां भी आपको मालूम ही है कि भ्रष्टाचार चलता है। नाफेड के अधिकारी भी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। उन्होंने प्याज की खरीद की थी। जिन लोगों ने कुछ दे दिया उनकी प्याज तो खरीद कर ली गई और बाकी लोगों की खरीद नहीं की गई। उनका एक डैपुटेशन भी यहां आया था और श्री मोहन धारिया से मिला था। मैं कहना चाहती हूं कि वहां जो भ्रष्टाचार है वह भी समाप्त होना चाहिए। जो हमारी जरूरत की चीजें हैं उनको एस टी सी नहीं तो नाफेड को सीधे प्रोड्यूसर से खरीदना चाहिए। शर्त यह है कि जो प्रोड्यूसर है उसको ठीक कीमत मिले।

आप गरीब आदमी का खास खयाल रखें। आप एक इनकम फिक्स कर दें। पांच सौ छः सौ या सात सौ से कम जिस किसी की आमदनी हो उसको आप सबसिडाइज़ करके जरूरत की चीजें दें। जो दरिद्रता की रेखा से नीचे रह रहे हैं उन लोगों को सबसिडाइज़ कर के आप इन वस्तुओं को दें। आप इम्पोर्ट के लिए कंसैशन देते हैं। आप जो प्रोड्यूस करता है उसको कंसैशन दें। इन दरिद्रता की रेखा से नीचे रहने वालों को आप सबसिडाइज़ करके उनको जरूरत की चीजें दें। आप इसके लिए कोई इनकम की सीमा बांध सकते हैं, उनके लिए अगर आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सैंटर्ज से इस तरह का प्रबन्ध कर देंगे तो जनता को और गरीब लोगों को कुछ राहत मिल सकेगी। नहीं तो भाव जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं उस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे।

रेडियो से आप घोषणायें करते हैं कि होलसेल प्राइसिस इतनी कम हो गई हैं या इतनी बढ़ गई हैं। लेकिन आप देखें

कि अगर होलसेल प्राइस 1 परसेंट बढ़ती है तो रिटेल प्राइसिस 25–30 परसेंट बढ़ जाती हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप इस तरह की घोषणायें रेडियो से करना बन्द कर दें। जो भाव रेडियो पर दिये जाते हैं, बाज़ार में हमें कभी भी वे भाव नहीं दीखते हैं। कभी-कभी हम देखते हैं कि कई चीजों के लिए हमें सुपर बाज़ार में बाहर से ज्यादा कीमत देनी पड़ती है।

मैंने सुना है कि किसी ने यह ऐलान किया है कि राशनिंग बंद होने वाला है। कृपा करके राशनिंग को बन्द न करें। हमें मालूम है कि आज राशनिंग में जो माल मिलता है उसको जानवरों के सिवा कोई नहीं खायेगा। बम्बई में जो चावल बारिश से ख़राब हो गया वही राशनिंग में दिया गया। उसकी क्वालिटी को सुधारना चाहिए।

पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सैंटर्ज़ के द्वारा केवल अनाज ही नहीं बल्कि कपड़ा, साबुन, तेल, मसाला और केरोसीन आयल आदि अन्य ज़रूरत की चीज़ें भी दी जानी चाहिए। इसके अलावा घर बनाने के लिए सीमेंट भी कंट्रोल रेट पर दिया जाना चाहिए। बम्बई में मज़दूरों के लिए मकान बन रहे हैं और 160 स्क्वेयर फ़ीट के लिए 160 रुपये भाड़ा तय किया गया है। सैंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसके लिए सबसिडी नहीं देंगे। स्टील और सीमेंट के दाम बढ़ने से भी महंगाई मे वृद्धि होती है। अगर सरकार सीमेंट को कंट्रोल रेट पर देने की व्यवस्था करे तो इससे भी लोगों को बहुत राहत मिलेगी। सरकार कहती है कि हम सबको गैस देने वाले हैं। वह उचित दाम पर दियासलाई तो दे नहीं पाई है गैस तो बहुत दूर की बात है।

जहां तक विजिलेंस कमेटी का प्रश्न है दिल्ली में भी महिलाओं की दक्षता समिति ने बहुत अच्छा काम किया है जिसकी सेक्रेटरी श्रीमती प्रमिला दण्डवते हैं। उसने अफ़सरों को बताया कि अमुक अमुक जगह पर होर्डिंग की गई है आप उसको देखें। बम्बई में महंगाई प्रतिकार समिति ने भी यही काम किया है। यह आवश्यक है कि दक्षता समिति को इंस्पेक्शन का अधिकार दिया जाए। अगर हम कहीं देखने के लिए जाते हैं तो वे लोग कहते हैं कि आप कौन हैं। बम्बई में ऐसा अधिकार दिया गया था जिसके कारण होर्ड किया हुआ तेल बाहर आ गया। विजिलेंस कमेटी को इंस्पेक्शन का अधिकार देने के अलावा अगर उनको लगता है कि कहीं पर होर्डिंग की जा रही है तो उनको पुलिस में शिकायत करने का अधिकार भी देना चाहिए। दक्षता समितियों को ये अधिकार देने से होर्डिंग और महंगाई की समस्या को हल करने में मदद मिल सकती है।

आखिर में मैं कहना चाहती हूं कि लोग तंग आ गए हैं। औरतें तो बहुत तंग आ गई हैं। औरतें हमें पूछती हैं कि हमारा बेलन कहां है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : किसको बेलन मारना है?

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : हमको मालूम है कि किसको मारना है। होर्डर्ज को बराबर यह बताया गया है।

श्री कंवर लाल गुप्त : उसको घर में इस्तेमाल न किया जाए।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : आपकी बीवी आपको कभी बेलन नहीं मारेगी।

मैं इशारे से कहना चाहती हूं कि अगर स्थिति में सुधार न हुआ तो हिन्दुस्तान की औरतों को एक दफ़ा फिर बेलन उठाना पड़ेगा।

MR. CHAIRMAN: Resolution moved:

"This House expresses its grave concern at the steep rise in the prices of all essential commodities like pulses, edible oils, milk, cloth, footwear, soap, etc. and fall in the prices of all commercial crops like sugarcane, cotton, tobacco, etc. and recommends that, with a view to protect the primary producers as well as the consumers, all essential commodities be procured through the State Governments at fair price from the producers and distributed to the consumers through an effective public distribution system supervised by People's Committees to be set up for this purpose."

MR. CHAIRMAN: Now Mr. Yuvraj is to move an amendment. He can speak later.

SHRI YUVRAJ (Katihar): I beg to move:

That in the resolution,—

(i) *after* "soap" *insert* "cement"

(ii) *after* "tobacco" *insert* "jute"

(iii) *add* at the end—

"and action be taken against malpractices and corruption in the distribution system on the basis of the reports received in this regard." (1).

MR. CHAIRMAN: Mr. Anant Dave is not present.

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur): I beg to move:

That in the resolution,—

add at the end—

"and parity be maintained in the prices of industrial products and agricultural commodities." (3).

SHRI V. M. SUDHEERAN (Alleppey): I rise to support the resolution moved by Shrimati Ahilya Rangnekar.

A very serious situation has developed because of the alarming rise in prices. As the mover of the resolution has already stated, the prices of all the essential commodities have risen. The common people, the middle class people, those who belong to the fixed income groups are the worst sufferers. The official wholesale price has taken a sharp upward turn during the last one month, upsetting all the calculations of the Finance Minister. The increase has been as much as 3.3 per cent in the month of June alone, of which 0.6 per cent was in the last week itself. This is equal to the worst days of price rise four years back.

The present Government has totally failed to check the price rise in all essential commodities. Although the Ministers concerned speak well, very cleverly, very beautifully prices have kept up their rise. Some of the essential commodities are not even available these days. The prices of pulses, edible oils, rice, wheat, fresh vegetables, kerosene, cement and all the essential articles have risen, and some of them are not even available in the market.

It is widely reported that hoarding and blackmarketing are taking place throughout the country. The hoarders and blackmarketeers are misusing the freedom prevailing in the country. Our Prime Minister had stated earlier that now there is freedom from fear, but it is very clearly indicated that now the hoarders, blackmarketeers and the anti-social elements are free from fear. They are taking advantage of the situation prevailing in the country. No adequate checks are there to prevent them from indulging in anti-social activities.

While the prices of industrial commodities are very high, agriculturists and cultivators are not getting a remunerative price for their produce. The paddy cultivators throughout the country are not getting remunerative

prices but the price of rice has gone up. The wheat cultivators are not getting a reasonable price for their produce, but the price of wheat has gone up. The tobacco growers are not getting reasonable prices for their produce, but the price of cigarettes and other items has gone up. The sugarcane growers are the worst sufferers. They are not getting reasonable prices for their produce, but the price of sugar has gone up, and it is not also available.

In Kerala we produce paddy, but our paddy producers and cultivators are not getting sufficient price, and they are put to trouble. I would like to point out the problem of the paddy cultivators of Kuttanad, the water-logged area of Kerala. The total area of Kuttanad is 1,25,000 acres with an annual yield of 3,000 tonnes of paddy. The 25,000 cultivators of Kuttanad are forced to boycott cultivation this year because their just and reasonable demands have not been properly met. They are not getting remunerative prices for their produce, while the cost of production is very high. Dewatering of the fields is the first among the various agricultural operations in the paddy belt. The fixation of the year's pumping subsidy is stated to be the most important issue concerning the cultivation of paddy. The paddy cultivators of Kerala also demanded a floor price for paddy and stoppage of all recovery measures in respect of the dues to the Government. The problem of cultivation in 5,000 acres of Karilland cultivation in my constituency near Alleppey, and the problem of the cultivation of the Kole land in Trichur have to be attended to.

The Kerala Government is very keen to solve all the problems, but the present financial position of the State Government is not sound enough to meet the just demands of the paddy cultivators of Kuttanad. Anyway, the Kerala Government has declared a support price for paddy. That is a welcome move. So, I would appeal to the Union Government to provide sufficient funds to the Government of Kerala to enable them to meet the just demands of the paddy cultivators of Kuttanad.

The Government of Kerala has declared a support price for tapioca also. That is a very welcome move. But the point is that the cost of production has increased much while they are denied reasonable prices. That is the phenomenon throughout the country. Whereas industrial manufacturers and traders are getting high profits, the poor peasants, the paddy cultivators, the wheat cultivators, the tobacco cultivators, the sugarcane cultivators are not getting sufficient or reasonable prices.

It is the evil influence of the monopoly houses on this Government, it is the evil influence of the traders and big businessmen on this Government that has led to the worst situation which is prevailing in the country. I am very sorry to say this, that the present Government is patronising the blackmarketeers, the hoarders, the monopolists that is why this situation has been created. So, I request the hon. Minister, through you, to take appropriate steps to check blackmarketing, hoarding and all this type of anti-social evils, and introduce an effective public distribution system.

Our Ministers have talked about introducing an efficient and effective public distribution system, but it has not been introduced so far. It is only a statement in the papers. What is this, Sir. Is it fair on the part of the Government to say something only in the papers and not implement it to meet the needs of the people? The people of this country are keenly watching what this Government is doing. If they are honest and sincere enough, they should take effective steps against hoarders, black-marketeers

[Shri V. M. Sadhasivam]

ers and other antisocial elements and introduce an effective distribution system. The people of this country, the common people, the labourers, the middle-class people are the worst sufferers because of the price rise. It is high time that this Government should take steps in this direction.

With these words, I support the Resolution moved by Smt. Ahilya Rangnekar.

MR. CHAIRMAN: There is a large number of hon. Members who want to speak on this Resolution. I therefore, request them not to take more than 7 minutes.

SHRI DINEN BHATTACHARYA (Serampore): I request you to kindly suspend the Rules so that I may be able to move my Resolution.

MR. CHAIRMAN: You move it at 5.30.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA (Faridkot): The Resolution which has been moved by an hon. Member of the House, needs sincere attention. It should be taken very seriously. The situation on the price front in this country is getting worsened day by day. The Hoarders and black-marketeers are having their heyday. I will humbly request that nothing will be gained by putting blame on this side or that side. If this House and the Members of this House are really loyal to their voters, loyal to the people in this country, to the poor people, kisans, low-income groups, fixed income groups, to the people who were hard, to those children who are working, we should take a bold stand unitedly against these hoarders and blackmarketeers as we take a united stand against the foreign invaders, who invade our territory.

Our Congress brothers have brought the heyday to these hoarders. They have taught them how to penetrate into the Government. Governments may change in the States, Governments may change at the Centre, but these people have trained them how to penetrate into the Government and how to get the things done. The Members of this august House should unite against the hoarders. Cement is being sold in black. See the position in Punjab. 17 railway trains have been cancelled. Yesterday, I raised this question in the House. Then many Members said that trains had been cancelled in their States also. On the one hand, the Railway Minister says, "We are surplus in wagons" and, on the other hand, the Energy Minister says, "we are surplus in coal" but the reason given by the Government for cancelling the trains is, "We are cancelling the trains because the coal is not there, the coal is in shortage". One is astonished at that. The Energy Minister in this House says, the coal is in abundance; the Railway Minister in the Rajya Sabha says, the wagons are in abundance. But the trains are being cancelled because the coal is not being supplied. This is the position of the Government. The Government must take the responsibility in this matter.

I would like to bring to the notice of this august House that in Punjab one good thing has been done. In Punjab, the State Government has opened 3000 cheap rate shops by the Food Corporation of the State. In these shops, for all the 12 months of the year, the Punjab Government has given the guarantee that *moong* will be sold at Rs. 3.40 per kg.; *mash*—Rs. 3.40 per kg.; washed *moong*—Rs. 4.00 per kg., washed *mash*—Rs. 4.00 per kg., mustard oil—Rs. 8 per kg., wheat and *atta*—Rs. 1.20 per kg., and ghee —Rs. 7.30 per kg. These are the essential items which are needed by the poor man. The Punjab Government has done it. Why not the Central Government also do it, if not in the States, at least in the union territories? The

Central Government should give the guidelines.

I would say that the trader of this country, the manufacturer of this country, the big industrialist of this country, is a blood sucker. They are sucking the blood of the poor, the worker, the peasant, the common man in the street. I would like to bring to the attention of the House as to how clever they are. Take, for example, the match industry. They say that they have reduced the price of a match box. They reduced the price of a match box by 2 p. but reduced the number of match sticks from 60 to 40 in the match box. Very cleverly, they say that they have reduce the price by 2 p. but the actual loss to the consumer is 6 p. The trader, the manufacturer, the industrialist, is a very clever person, a cheat. a professional person, who knows how to cheat, how to deprive the consumer of his money.

All emphasis is being given on packaging. The things inside are of very inferior quality. Inferior quality things are packed in very good packages. They are sold at high prices. The Government should issue strict orders saying that the packaging should be very simple. At least the advertisement cost should not be included in the manufacturing cost.

Lastly, in my constituency, the American cotton growers are being fleeced. In Faridkot, Jaitu, Malot, Bhatinda, Mukatsar, Rampuraphul, Rama, etc., in those areas of Punjab the American cotton is produced. In 1977, the price of American cotton in these mandis was Rs. 500. This year, it was Rs. 250.

17 hrs.

The textile owners are destroying the economic of the poor peasants. The poor peasants are at the mercy of these textile owners. I will humbly request the Government to give Rs. 200 crores interest free to the Punjab Government to enable them to start their own cotton corporation so that Punjab Cotton Corporation may come to the rescue of these poor peasants.

In the end, I will humbly request this House—I hope everbody will support me very seriously—that this House should tell the Government to appoint a commission consisting of Members of Parliament—not Shah Commission or any other commission —and that commission should go into details. They should compare the increase in prices between the agricultural commodities and the industrial output. In my opinion, in the last eight years, the prices of agricultural commodities have risen 20 per cent whereas the prices of industrial products like tractors, tube-wells, machinery, pesticides and fertilisers, have risen by 300 per cent. With these few words, I conclude my speech. I am thankful to you.

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के समक्ष है उसका सिद्धान्त रूप में मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि यह तो हरेक व्यक्ति स्वीकार करेगा कि चीजों के भाव नहीं बढ़ने चाहियें। चीजें सभी को ठीक दाम पर मिलनी चाहियें, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। पर अभी कांग्रेस के मेरे भाई जनता पार्टी को कह रहे थे और अहिल्या जी भी जनता पार्टी को कह रही थी कि हम मल्टीनेशनल कम्पनीज के साथ हैं, होर्डर्स के साथ मिले हुए हैं और ब्लैक मार्किटियर्स के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई बहुत ज्यादा है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वस्तु-स्थिति क्या है?

देश में अप्रैल, मई और जून 1976 में प्राइसिज में 3.2 परसेंट की इंक्रीज हुई

[श्री कंवर लाल गुप्त]

थी। इन तीन महीनों में, 1977 में यह इंक्रीज 2.3 परसेंट की हुई। 1978 के इन तीन महीनों में यह इंक्रीज 1.6 परसेंट की है। इसका मतलब यह है कि 78 से अब जो दाम बढ़े हैं वे करीब करीब आधे बढ़े हैं। यह कहने का मेरा मतलब यह नहीं है कि दाम बढ़ने चाहियें। लेकिन मेरा कहना यह जरूर है कि कीमतों के मामले में, देश में पहले से हालत खराब है, यह कहना तथ्य से परे है, ठीक नहीं है। यह बात वही लोग कह सकते हैं जो सच्चाई को नहीं जानते या तथ्यों की जिन्हें जानकारी नहीं है।

हाल में मुझे विदेश जाने का मौका मिला। इस साल तीन महीनों में हमारे यहां 1.6 परसेंट प्राइस इंक्रीज हुई। अब जरा देखिए कि इंग्लैंड में कितनी हुई एशिया में कितनी हुई और अमेरिका में कितनी हुई?

I went to Russia. There is an open market in Moscow: otherwise it is all controlled by the Government. There is only one open market, the vegetable market, in Moscow. I returned only three weeks back: there the prices of tomato was Rs. 25- a kilo and similar is the case with onions. Even for ordinary vegetables, I was told, prices have gone up by three to four times in Moscow. If I am wrong, I am prepared to take the responsibility and give a public apology. But the fact remains. You may go to England, America or any other country; the speed of rise in prices is much more than in India.

कहने का मतलब यह नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वह बिल्कुल तसल्लीबख्श हो रहा है और उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। सुधार की गुंजाइश है और बहुत है। सौभाग्य से हमारे पास दो बातें बहुत अच्छी हैं। हमारे पास बफर स्टाक काफी है। हमें इस बात की चिन्ता नहीं है कि अगर अनाज की कमी पड़ेगी तो कहां से आएगा। हमारे पास 17–18 मिलियन टन अनाज है। साथ ही साथ हमारे पास एक दूसरा हथियार भी है। हमारे पास फारेन एक्सचेंज काफी है। अगर किसी चीज का अभाव होता है तो उस चीज को हम विदेशों से मंगा सकते हैं और देश में उस चीज को सुलभ कर उसके दाम ठीक कर सकते हैं। इन दोनों हथियारों के होते हुए भी मैं समझता हूं कि सरकार को और ज्यादा एफिशेंसी दिखानी चाहिए। इसमें दो रायें नहीं हैं।

आज चीजें तो मिलती हैं इसमें शक नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो थोड़ी मात्रा में हैं और उनकी शार्टेज है। सीमेंट की है, कोल की है। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा टाइटन करने की जरूरत है। मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं।

The supply of statements by the Minister is much more. It should be reduced and supply of commodities should be more.

मंत्रियों के स्टेटमेंट कुछ कम होने चाहियें और सप्लाई ज्यादा। आज चीजों की सप्लाई जरा कम्पैरेटिवली कम है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप पहले कर दें और बाद में बोलें। आज होता यह है कि पहले आप स्टेटमेंट दे देते हैं लेकिन बाद में वह चीज पूरी नहीं होती है। इसका अच्छा असर नहीं होता है। मैं आपसे गिनाना नहीं चाहता हूं। मेरे पास बहुत से आपके स्टेटमेंट्स हैं। मैं यही कहना चाहता हूं :

Kindly reduce the supply of statements and increase the supply of commodities. That is the only remedy.

आपने अब तक अच्छी बातें ही कही हैं। आप देखें कि उनका इम्पैक्ट कितना हुआ है। जितना होना चाहिये था नहीं हुआ है। भावों पर और सप्लाई में उसका पड़ा है।

तेल के मामले को ही ले लें। पिछली सरकार ने तेल के मामले में बहुत बंगलिंग किया। करोड़ों रुपयों के लाइसेंस दिये और लोग उनको डकार गए। उन से पैसा ले लिया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। परिणाम यह है कि तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। इस सरकार के आने के बाद हमने तेल के परमिट्स दिए। यहां तेल आया, रैप सीड आयल आया ....

AN HON. MEMBER: This Government is repeating the mistakes of the earlier Government.

श्री कंवर लाल गुप्त : इस सरकार ने तेल की सप्लाई रेगुलर तरीके से की और उसको देश के कोने-कोने में ठीक दाम पर पहुंचाया, लेकिन एक शिकायत मेरी इस बारे में भी है और वह यह है कि इस सरकार के समय में जिन लोगों ने बंगलिंग की थी उस पर कुछ पर्दा पड़ गया है। वह पर्दा क्यों पड़ गया है, यह तो मंत्री महोदय जानें इन में से कई केसेज की इन्क्वायरी सी०बी०आई० कर रही थी, उनका क्या हुआ? क्या उन में से कोई केस अदालत में गया या नहीं? अगर सरकार ब्लैक मार्किटियर्स के खिलाफ कार्यवाही करना चाहती है, तो उसको ऐसी परम्परा डालनी चाहिए कि वह बड़े बड़े लोगों को एक्जेम्पलरी पनिशमेंट दे। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती।

हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा बिलो-पावर्टी लाइन है। सरकार को इस बात की गारन्टी देनी चाहिये कि अनाज, तेल, कपड़ा, दालें आदि जो 8, 10 एसेंशियल कमोडिटीज हैं, वे बिलो-पावर्टी लाइन के लोगों को एक निश्चित दाम पर जरूर मिलेंगी और चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी सब्सीडाइज करने की जरूरत क्यों न पड़ जाय, वह किया जायेगा, लेकिन उन चीजों के दाम नहीं बढ़ाये जायेंगे।

दिल्ली में हम लोग राशन में गेहूं और चावल लेते हैं, अगर हमारा राशन बन्द भी कर दिया जाये तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जो लोग बिलो पावर्टी लाइन हैं, उनके लिए गारन्टी होनी चाहिये कि चाहे काश्मीर हो या कन्याकुमारी, कोई ड्राइबल एरिया हो या दिल्ली, देश में हर जगह उनको एसेंशियल कमोडिटीज एक पर्टिकुलर प्राइस पर मुहैया की जायेंगी। दाम चाहे कितने भी बढ़ जायें, लेकिन उन लोगों को वे चीजें उन्हीं दामों पर मिलेंगी, इस बात की गारन्टी होनी चाहिये।

हमारे देश में अभी तक जो डैवलपमेंट हो रहा है, उसका ज्यादा फायदा ऊपर के लोगों को मिल रहा है। सरकार गांव में इलैक्ट्रिसिटी दे रही है, बड़े-बड़े जमींदार ही वहां उसका उपयोग करते हैं। सरकार को इलैक्ट्रिसिटी पर 200 करोड़ रुपये सालाना का लास होता है। इसी तरह से इरींगेशन पर भी सैकड़ों करोड़ रुपये का लास हो जाता है। इससे फायदा किसको हुआ है? छोटे लोगों, लैंडलेस हरिजनों, छोटे किसानों को इसका फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि न वह इलैक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं और न उनके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज हैं, सिर्फ बड़े लैंडलार्ड्स को ही इसका फायदा होता है। इसलिये सरकार को देखना चाहिये कि गांवों और शहरों में जो डेवलपमेंट होता है उसका ज्यादा लाभ नीचे के तबके के पास पहुंचे। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है और हमारा समाजवाद भी खोखला रह जायेगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा।

मैंने श्री धारिया को एक चिट्ठी लिखी थी—इस बारे में पहले भी चर्चा हुई थी—कि रा-मैटीरियल का जितना दाम बढ़ता है क्या उसी हिसाब से कंज्यूमर को मिलने वाली चीजों का भी दाम बढ़ता है? मैंने

श्री कंवर लाल गुप्त :

25 चीजें बताई थीं कि उन चीजों के रा मैटीरियल की कीमत तो गिर गई, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने कंज्यूमर गुड्स के दाम बढ़ा दिये। मैंने कम्पनी का नाम भी लिखा था। क्या सरकार के पास कोई कास्टिंग डिपार्टमेंट है या नहीं? उसे अपने कास्टिंग डिपार्टमेंट को मजबूत करना चाहिये। अगर रा-मैटीरियल का दाम न बढ़ने के बावजूद मैन्युफैक्चरर अपनी चीजों के दाम बढ़ा देता है तो उसका गला पकड़ना चाहिये और उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि हर एक लेवल पर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर के लेवल पर सीलिंग आन प्राफिट तय होना चाहिये।

यह तो नहीं होना चाहिये कि लूट हो रही है जो मर्जी जिसकी आए करे। मैं एक नहीं पचासों उदाहरण दे सकता हूं कि जहां पर रा-मैटीरियल के दाम नहीं बढ़े लेकिन इण्डस्ट्री वालों ने बढ़ा दिये, होलसेलर्स ने बढ़ा दिए और रिटेलर्स ने बढ़ा दिये। आप एक सीलिंग आन प्राफिट हर एक लेवेल पर करिए और कास्टिंग करिए ताकि जहां जितना रा-मैटीरियल का दाम बढ़े उतना ही दाम बढ़ाने की उनको आज्ञा दीजिए। उससे ज्यादा बढ़ाने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए।

एक और चिन्ता की बात है वह यह है कि मनी सप्लाई हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसकी वजह से अभी दाम नहीं बढ़े लेकिन उसका असर आगे जाकर पड़ेगा। इस समय हर एक राज्य ओवर-ड्राफ्ट कर रहा है। जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा कि केरल को और पैसा दो, केरल का भी ओवर-ड्राफ्ट है और हर एक स्टेट का ओवर-ड्राफ्ट है। उससे यह होगा कि महंगाई बढ़ेगी तो इकोनामिक मिनिस्ट्री के साथ एक कोआर्डिनेशन होना चाहिए। इकोनामिक मिनिस्ट्री के साथ कोआर्डिनेशन के साथ मनी-सप्लाई कम करनी चाहिए। मेरे मित्र ने केरल की बात कही और वैस्ट बंगाल की बात कही। मैं पूछना चाहता हूं, वहां तो जनता पार्टी की सरकार नहीं है! वैस्ट बंगाल में क्या यह सही नहीं है कि बिरला, टाटा और बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को वहां के चीफ मिनिस्टर ने बुलाकर कहा कि आप यहां इण्डस्ट्री लगाइए!

Then don't accuse the Janata Party for God's sake. You invite these big industrialists and give thm all facilities and yet you accuse us.

Even in Kerala it is the same. What action have you taken? After all public distribution is the work of the State Government. What specific steps have you taken in Kerala? Practically nothing and you only accuse us and say, 'Give us money and we will distribute.' That is a very easy thing. Why don't you produce money?....

SHRI V. M. SUDHEERAN: We are producing rubber, tea, cardamom and so many other things and we earn a substantial foreign exchange for the country.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: You have not levied any tax on big landlords. I accuse you.....

SHRI V. M. SUDHEERAN: Guptaji is ignorant of Kerala. Kerala is the first State to implement land reforms. I invite Mr. Gupta to come to Kerala and study Kerala.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I will come.

मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि आप पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को थोड़ा और ज्यादा करिए, मास-कंजम्पशन की चीजें पब्लिक सैक्टर में भी बनाइये। जब तक आप पब्लिक सैक्टर में मास-कंजम्पशन की एसेंशियल कमोडिटीज नहीं बनाएंगे तब तक उसके दाम ठीक नहीं होंगे। इसको भी रेगुलेट कीजिए। मैं यह नहीं मानता कि सारी चीजें सरकार ले ले। इतना सरकार

के पास पैसा नहीं है । केवल एक आइटम गेहूं ले रखा है जिसमें 2200 करोड़ रुपये लगे हुए हैं । क्या जो कम्यूनिस्ट भाइ, कहते हैं कि ठीक है वरना बीच का रास्ता नहीं है । आप सारे आइटम लेकर 65 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम नहीं कर सकते हैं । इसलिए जो फ्रीडम फ्राम मूवमेंट है फूडजोन्स की. मैं उसका स्वागत करता हूं जो जनता पार्टी ने किया है । बम्बई में जब हम जाते थे तो हमारे रिश्तेदार कहते थे कि दो किलो अच्छा चावल साथ लाना । अब नहीं कहते । अब वहां चावल मिलता है । तो मेरा कहना यह है कि हमने कुछ अच्छे कदम भी उठाए हैं, उसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप जो बिलो-पावर्टी लाइन के लोग हैं उनके लिए गारंटी कीजिए कि इतनी कीमत के ऊपर हम हर एक को देंगे । बाकी जगह दाम बढ़ भी जायें लेकिन उनके दाम नहीं बढ़ेंगे । इस विश्वास के साथ मैं इसका सिद्धान्त रूप से समर्थन करता हूं ।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Shrimati Ahilya P. Rangnekar has brought a timely resolution which will help the government to know where it stands, if it wants to know. From the speeches of my friends it is clearly stated that the consumer prices are going up. The producers' prices are coming low and the traders and the middlemen are exploiting the nation. If it is so, then this should be corrected by the Government.

With regard to peasants I want to tell certain things. After the advent of Janata Party almost all the prices of agricultural commodities are going down. It is because this Government prohibited the exports of agricultural commodities, even the vegetables. That is why the prices are going down.

With regard to gur, what is happening? It was Rs. 180/- per quintal before Janata Party came to power. Now it is Rs. 60/- per quintal. Therefore, it is slightly more than 1/3rd.

What about Coriander? It was Rs. 300/- per bag. Now it is Rs. 90 per bag. What about tobacco? It was selling at Rs. 10/- per kg. Now it is Rs. 3/- to Rs. 4/-. What about paddy? What about wheat? Support prices are declared. Whether they are remunerative or not the agricultural Price Commission declared support prices. But whether the surpulses are purchased or not is the question? Where are the surpluses of wheat and paddy in our country? Shri Mohan Dharia himself has stated that there are surpluses in Andhra Pradesh and there are deficits in other States. That means that the procurement and distribution system is not perfect in this country according to the Minister's statement. Therefore, is it not necessary to correct that? Now when the prices of agricultural commodities are going down can the Government keep quiet? My friend here has said that in Kerala where there is deficit in food grains the agricultural producers are suffering very much especially the paddy growers. What happened in Andhra Pradesh? When cyclone came the paddy growers suffered very much, but the Central Government refused to purchase paddy. Even there, as in Kerala, the State Government has to bear the brunt of purchasing paddy. Why is this Government shedding responsibility of protecting the agriculturists in States? It is its responsibility to purchase these things and to stabilise the prices. Therefore, there must be a solution. What is the solution?

There is the Agricultural Price Commission in our country. It has been constituted in 1965. Till now it is not reconstituted and, therefore, I request the hon. Minister to see that it is reconstituted immediately. Agricultural price Commission is not having proper representation of the

[Shri P. Rajagopal Naidu]

agriculturists. There is only one representative—i.e., from wheat zone. There is no representative at all for paddy—which is the largest growing area in our country. Therefore, when it is reconstituted, it must have proper representation of the producers so that remunerative prices are fixed. They say, support prices are being paid. Well, what is the support price which the Agricultural Prices Commission is fixing? This is my question. What is the basis? There must be a basis for these things. The basis for the fixation of the support price must be that the price must be remunerative to the farmers. It is not remunerative at all. The APC should be asked not to fix up any unremunerative price. This is my submission. They should fix up only remunerative price.

Then, my next point is this. All the surpluses must be bought by the Government. There must be suitable machinery provided for this purpose. There must be enough number of godowns also. There must be a comprehensive plan for this purpose. Where is the plan for it? There is nothing in this regard in the fifth plan or the sixth plan. The Janata Government is boasting that it is for the rural people, it is for the kisans and so on and the agricultural people. But what is happening here? What is being done is nothing but depring the agricultural classes of their dues. If the Government in really and sincerely interested in coming to the rescue of the agriculturists, then, I submit, Sir, that they must reconstitute the Agricultural Prices Commission and they must buy all their surplus. This is my respectful submission.

Sir, we are becoming surplus in wheat. We are becoming surplus in rice. Are we exploring the markets outside? There must be necessary export promotion work undertaken in this behalf. We should develop our Export Promotion Council in this regard.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: Sir, I would like to move a Motion for suspending the Rules, so that I may move my Resolution which is No 8 in the List.... (*Interruption*).

MR. CHAIRMAN: Order please. You are a senior Parliamentarian, Mr. Dinen Bhattacharya. You know the Rules of Business very well. This discussion will continue upto 5-30. Then we have Half-an-hour discussion after that. Your Resolution is there and that will be taken up on the next day allotted for the Private Members' Resolutions.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: I will just move my Resolution. I will not speak.

MR. CHAIRMAN: Mr. Dinen Bhattacharya, you understand all these things. You are a senior Member; you are a senior Parliamentarian.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: With regard to the distribution of essential commodities, what is the Government doing? The Government is always very particular about the organised classes and about the town people, and about the white-collared people. It is not at all caring for the small farmers, the agriculturists or the small artisans. It is not caring for these poor people in the villages.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: Sir, in the case of Mr. Samar Guha's Resolution, the same thing was done. Certain other Resolution was under discussion. That was postponed for the time-being, for two minutes or so. Mr. Samar Guha moved that Resolution standing in his name.

MR CHAIRMAN: If it was moved it was discussed on the next day.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: In the countryside, they are not getting cloth they are not getting kerosene, they are not getting diesel oil, they are not getting their agricultural implements.

MR. CHAIRMAN: Mr. Rajagopal Naidu, you will continue on the next day, allotted for Private Members' Business.

We pass on to the next item

SHRI DINEN BHATTACHARYA: Will you permit me to move my Resolution, Sir?

MR CHAIRMAN: You know the rules. You know everything. You are teaching many Parliamentarians. Please don't break the rule.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: You can suspend the Rule....

MR. CHAIRMAN: Please resume your seat, Mr. Dinen Bhattacharya. I appeal to you.

Now, we will go to the next item.

RE: CORRESPONDENCE BETWEEN THE PRIME MINISTER AND THE FORMER HOME MINISTER

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Before you go to the next item, I would like to make my submission on a Point of Order.

We have just come to understand that something has been decided about the correspondence between the Prime Minister and the former Home Minister.

I hope you know that there was a lot of discussion in this House. Now information has reached us—it is for you to contradict it if it is wrong. But, it has reached us that several honourable colleagues of ours who are representing various groups are being invited to the Speaker's Committee Room to inspect the correspondence.

Now, I want to know whether it is a fact. If so, want to raise an objection on two grounds—firstly, have you ever decided this matter in the House; all that I know of is the fact that this was being discussed when the matter was kept pending until the Speaker decided and informed the House. Now, we have not disposed of this matter; nor have we got any finality from the hon. Speaker. I am told in the other House, the hon. Chairman of the House, decided the course of action and they are doing it. Now it is not for us to comment upon what happened in the other House. It will not be right and proper to do that also. But my point is that if something happened in that House and the same thing is being repeated here without the knowledge of the House by the hon. Speaker about the whole position, is it in order? This is my point number one. Secondly, how is it that only some are invited? I do not know why I have not been asked for it. In the other House, some Independents have been invited. In the other House some Independents have also been asked to see it. I have not got any information. All I am saying is, this is a point on which I stand on principle.

No announcement was made. I have no information; I have no intimation. Apart from that, my main point is that the House has not been kept informed about this at all; the House has not been taken into confidence; nor has the Speaker given us any decision. And if something happens without all this in the Speaker's Committee Room, I may sorry; I must raise my voice of protest.

I want your guidance from you.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Mr. Chairman, may I make a submission? The matter was raised in the House and almost all the Group Leaders were associated with the demand for the papers; the exchange of letters to be placed either on the table of the House or in the manner in which it was thought fit. Now, whatever the decision taken, I